(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । ये स्कीमें नेपाल की महामहिम सरकार जिनके क्षेत्र में ये परियोजनाये स्थित हैं, की सहमति से ही कार्यान्वयन हेतु हाथ में ली जा सकती हैं। भारत सरकार इस संबंध में नेपाल की महमहिम सरकार के साथ बातचीत कर रही है ।

बिहार में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का नहरों द्वारा जोड़ा जाना

800. **श्री राम भगत पासवान :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 से अब तक केन्द्र सरकार ने बिहार की सिंचाई के लिये कितनी राशि आवंटित की है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार हमेशा सूखे और बाढ़ों से प्रभावित होता रहा है, यदि हां, तो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को नहरों से जोडने के लिये कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने में कितने वर्ष लगने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) सिंचाई एक राज्य-विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये धन-राशि की व्यवस्था राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है । केन्द्रीय सरकार सिंचाई परियोजनाओं के लिये धनराशि आवंटित नहीं करती है। बिहार सरकार ने योजना अवधि के आरम्भ से लेकर मार्च, 1982 के अन्त तक बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर 904 करोड़ रुपये व्यय किये हैं । इसके अतिरिक्त उन्होंने लघु सिंचाई परियोजनाओं पर लगभग 246 करोड़ रुपये व्यय किये हैं ।

(ख) यह सच है कि बिहार बाढों और सूखा से प्रभावित होता रहा हैं । राज्य सरकार ने पहले ही अनेक सिंचाई परियोजनायें एवं बाढ़ नियंत्रण उपाय हाथ में लिये हुए हैं । अन्ततः सृजनीय 12.40 मिलियन हैक्टेयर की क्षमता की तुलना में , 5 23 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता जून, 1982 तक पहले ही सृजित की जा चुकी है । इसी तरह से, 16.26 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की बाढ़ों से उचित सुरक्षा व्यवस्था की जा चुकी है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी निर्माणाधीन, तथा भविष्य में हाथ में ली जाने वाली सिंचाई स्कीमों के अन्तर्गत, नहरों और तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य सीमा तक अन्य उपायों द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इस समय यह कल्पना की गई है कि अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता सन् 2000 ई० के अन्त तक सृजित कर ली जायेगी ।

Subarnaekha Irrigation Project

801. SHRI SHYAM SUNDER MOHAPATRA : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) what is the present position of the Subarnarekha Project in Orissa; and

(b) to what extent it will help the flood protection and irrigation ?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDEY) : (a) Subarnarekha Project of Orissa was considered by the

Advisory Committee of the Planning Commision in its meeting held on 30-6-1982 and the project was found acceptable subject to certain conditions. Formal approval of the Planing Commission is awaited.

(b) The Project on completion will provide annual irrigation to an area of 1.66 lakh hectares. This project, as such, will not afford any benefits of flood control. However, the Dam proposed in Bihar in which a specific provision of Head Storage, has been made together with construction of flood embankments in Orissa are expected to benefit an area of 0.8 lakh hectares in Orissa.

Land under Irrigation

802. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) the total area (in acres) under irrigation, from major, medium and minor irrigation schemes, as at the end of 1976-77 and 1981-82, State-wise;

(d) what is the area under irrigation as percentage of total cultivated area, State-wise, at at the end of 1976-77 and 1981-82; and

(c) what financial and other assistances have been given to States in this regard ?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDEY) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Centrally Sponsored Multi-Purpose River Valley Scheme

803. SHRIMATI KANAK MUKHERJEE : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) the details of the centrally sponsored multi-purpose river valley schemes currently under implementation in each State;

(b) what is the irrigation potential of each of the schemes; and

(c) what is the progress made so far ?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDEY) : (a) There are no centraliy sponsored multipurpose river valley schemes.

(b) and (c) Do not arise.

Selection Board for Hindi Officers in CWC

804. SHRI M. BASAVARAJU : Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representative of the Ministry of Home Affairs who was included in the Selection Board as a Member for appointment of Hindi Officers in the Central Water Commission did not attend the said meeting of interview;

(b) what are the reasons for his not attending the said meeting when he was included as an expert and that the selection was made in the absence of experts;

(c) whether the above appointments are proposed to be cancelled in view of the above and fresh appointments made according to the instructions of the Ministry of Home Affairs, if so, by when; and

(d) if not, what are the reasons therefore ?

THE MINISTER OF IRRIGATION (SHRI KEDAR PANDEY) : (a) Yes, Sir;

(b) An officer of the Department of Official Languages was one of the five Members of the Selection Committee. He was not included in the Committee in the capacity of an expert. He could not however, be available to attend the meeting of the Selection Committee due to unavoidable reasons.

(c) and (d) Do not arise.